'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

प्रकाशन तिथि–28 फरवरी, 2013

DL(ND)-11/6144/2013-14-15

R.N.I. No. 68180/98

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 7 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 28 फरवरी, 2013

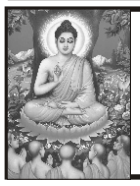

जहां मन हिंसा से मुड़ता है, वहां दुःख अवश्य ही शांत हो जाता है।

-गौतम बुद्ध

जम्मू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लिए अहम फैसले

डॉ. उदित राज

17 फरवरी को प्रादेशिक सम्मेलन संपन्न होने के उपरांत नेशनल स्टियरिंग कमिटी की बैठक शुरू हुई और 18 फरवरी को तीन बजे तक चला। इस बार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के मुद्दे इस तरह से थे कि कैसे नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित किया जाए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, कैडर लगना जरूरी है और दलित–आदिवासी व्यापारियों को संगठित करना। गत् कई वर्षों से परिसंघ निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन जिसको इसका लाभ मिलने वाला है उन्हें हम संगठित करने में असफल रहे हैं। परिसंघ का नेतृत्व भी पुराना होता जा रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सेवानिवृत हो गए हैं। जिस तरह से नेतृत्व सेवानिवृत हुआ है उस अनुपात में नए लोगों को नहीं जोड़ा गया, यह हमारी भूल भी रही है। निजीकरण की वजह से नौकरियां वैसे भी कम हो गई हैं और दूसरी तरफ शिक्षित नौजवानों की संख्या बढी है तो ऐसे में निजी क्षेत्र में आरक्षण कितना जरूरी है, समझना मुश्किल नहीं है। अन्ना का आंदोलन हो या अरविंद केजरीवाल का और हाल में निर्भया बलात्कार और हत्या का संघर्ष, इनमें नौजवानों और विद्यार्थियों की भागीदारी अहम रही जबकि इनके मुद्दे विद्यार्थियों और नौजवानों को सीधे प्रभावित भी नहीं कर रहे थे। दुःख की बात है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दलित–आदिवासी नौजवान एवं छात्रों को सीधे ही प्रभावित नहीं कर रहा बल्कि उनका पूरा भविष्य इस पर निर्भर कर रहा है। हालत आज यह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं तो पढ़ाई है बेकार। गत् 10 जनवरी को नांदेड़, महाराष्ट्र में हर्षवर्धन दवणे के नेतृत्व में विशाल सम्मेलन हुआ और संकल्प लिया गया कि इस वर्ष में देश के एक लाख विद्यार्थियों और नौजवानों को संगठित किया जाएगा। हमारे आंदोलन से सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने स्तर पर इन्हें संगठित करते हुए सूचित करें।

लगातार 15 साल से हम ईमानदारी से तमाम अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। पूरे साल हमारी ऊर्जा संघर्ष में ही लगी रही जिसके वजह से कैडर कैंप इत्यादि नहीं हो पाए। कैडर किसी भी आंदोलन का वह भूमिका निभाता है जैसे शरीर में रक्त प्रवाह करने वाली नाड़ियां। कुछ कर्मचारी एवं अधिकारियों ने कैडर बनाने की मुहिम को बदनाम भी बहुत किया है। वे लगातार कैडर चलाते रहे, चंदा वसूलना उनका मुख्य धंधा हो गया है और साल में एक सम्मेलन। ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करने में माहिर लेकिन संघर्ष के नाम पर जीरो। इस कथन से कौन नहीं परिचित है कि सिद्धांत के बगैर व्यवहार का ज्यादा मतलब नहीं है और व्यवहार के बगैर सिद्धांत भी निरर्थक है। हम सिद्धांत और व्यवहार दोनों का सामंजस्य बनाकर के आगे बढ़ते रहे लेकिन कार्यकर्ताओं को जिस तरह से शिक्षित और दीक्षित करना चाहिए था, ना किया जा सका। यह कार्य कैडर कैंप और शिविर के माध्यम से ही किया जा सकता है। अभी तक हरियाणा, जम्मू एवं उत्तराखंड ने कैडर कराने की जिम्मेदारी ली है। लोगों से यह भी कहा गया है कि अपने–अपने सुझाव भेजें कि कैडर करने के लिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार किस तरह के ज्ञान और सामग्री की आवश्यकता है। माह मई तक सभी राज्यों को कैडर करा लेना है।

राष्ट्रीय अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल रात–दिन वही खबर दिखा रहे हैं जो ब्राह्मणवाद को मजबूत करे। कहीं से कोई किसी भी विवादित वक्तव्य को लेकर के रात–दिन उसी पर चर्चा चलाते रहते हैं जिसका मतलब ना आम जनता के समस्या से है, किसान तो इनकी वरीयता में तो आते ही नहीं, दलित–आदिवासी की खबर देना तो दूर की बात उल्टा आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाने का काम जरूर करते हैं। एक समय था जब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता एवं नेताओं के काम करने की बात उठती थी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने उसके भी महत्व को कम कर दिया। सेकेंडों एवं मिनटों में अपने वर्ग के नेता की बात पूरे देश के कोने–कोने में पहुंचा देते हैं। ऐसे में जमीनी कार्यकर्ता की बात कितनी दूर तक पहुंच पाती है। हाल में कांग्रेस ने जयपूर में चिंतन शिविर रखा और उसमें भी सोशल मीडिया के उपयोग की बात जोरो से उठीं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होकर के सोशल मीडिया के महत्व को समझती है लेकिन हम इससे अंजान बने हुए हैं। जब मुख्य धारा के अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल हमारी बात को नहीं उठाएंगे तो सोशल मीडिया के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता। स्वाभिमान के साथ यदि देश में जिंदा रहना है तो सोशल मीडिया को जीवन का हिस्सा मानकर के चलना ही होगा। यह सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली मीडिया है। फेसबुक, इंटरनेट, टिव्टर, एसएमएस, मिस्ड कॉल, वेबसाइट आदि सोशल मीडिया हैं और जितनी जल्दी ही इसका उपयोग अपने विचार एवं आंदोलन के प्रचार–प्रसार के लिए करेंगे उतनी ही रफ्तार से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। परिसंघ के सभी कार्यकर्ता एवं वॉयस ऑफ बुद्धा के पाठक जल्द से जल्द अपना ईमेल एवं मोबाइल हमें मेल करें ताकि उनका डाटा बैंक बनाया जा सके और मिनटों में अपनी बात देश के कोने–कोने में पहुंचाया जा सके।

बहुत पहले की बात नहीं है कि जब यह माना जाता था कि राजनीतिक सत्ता की वह कुंजी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं लेकिन अब वह उतनी सच नहीं रह गयी। निजीकरण एवं ध्रुवीकरण की वजह से बड़े–बड़े औद्योगिक घराने खड़े हो गए हैं। राजनीति में काले धन का उपयोग बहुत बढ़ गया है जिसकी बहुत हद तक पूर्ति व्यापारियों के काले धन से होता है। जब राजनैतिज्ञ लोग इनसे सहयोग लेंगे तो मजबूर होकर के बात माननी होगी। यही वजह है कि तमाम सारे नीति एवं कानून पूंजीपतियों के पक्ष में बन रहे हैं। जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठती है तो विरोध उद्योग जगत से ही होता है। इतना ही नहीं बल्कि मुश्किल और आगे बढ़ जाती है जब हम अपने छोटे–मोटे आंदोलन को आर्थिक अभाव में चलाने में असक्षम बने रहते हैं। सवर्ण पूंजीपति भला हमें क्यों संसाधन देंगे बल्कि वह उनको देंगे जो हमारे विरूद्ध हैं। ऐसे में अपने समाज से ही कारोबारी पैदा करना पड़ेगा। सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में कुछ काम तो हो गया है लेकिन आर्थिक मोर्चे पर शुरुआत तक नहीं हो पाई है। निजीकरण की वजह से आरक्षण तो खतरे में है और हम अपनी इस मांग को पूरा कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हमें अपने छोटे कारोबारी का संगठन बनाकर उन्हें शिक्षित, प्रशिक्षित, ज्ञान, सरकारी सुविधाएं आदि से अवगत कराना होगा ताकि ये भी उद्योगपति बन सके। परिसंघ के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जहां तक संभव हो अपने कारोबारियों से बात करके संगठित करें और उनके नाम और पता भी हमें अग्रसारित करें। हमें जल्द ही कंफेडरेशन ऑफ दलित इन्टरप्रेन्योर की शुरुआत करनी है।

बांये से दांयेः आर. के. कलसोत्रा, डॉ. उदित राज(राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ), इंदिरा अठावले

परिसंघ के सभी कार्यकर्ता एवं वॉयस ऑफ बुद्धा के पाठक जल्द से जल्द अपना ईमेल एवं मोबाइल हमें मेल करें।

जम्मू में परिसंघ ने लिया अहम फैसला

डॉ. उदित राज के भाषण को सुनती भीड़

भीड़ को संबोधित करते डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष,परिसंघ

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ (जम्मू ईकाई) ने 17 फरवरी को गुर्जर ट्रस्ट में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर देश में ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। 26 अक्टूबर, 1947 को इसको भारत का अंग माना गया। एक तरफ यह प्रदेश भारत का अंग है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को फिर से वहां की विधान सभा में पास कराया जाता है। वहां के एससी/एसटी कर्मचारी–अधिकारी वरिष्ठता एवं परिणामी लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। वहां पर हाई कोर्ट ने नागराज के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं माना और कैचअप रूल लागू कर दिया। कैचअप रूल का मतलब यह है कि भले ही एससी/एसटी के कर्मचारी–अधिकारी पदोन्नति में आरक्षण की वजह से वरिष्ठ बन जाते हैं लेकिन वे तब तक आगे पदोन्नति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि सामान्य वर्ग के कर्मचारी–अधिकारी, जो पहले साथ थे, इस पद पर पहुंच नहीं जाते। 85वां संवैधानिक संशोधन द्वारा वरिष्ठता एवं परिणामी लाभ को बहाल किया लेकिन इस प्रदेश में अभी तक नहीं लागू हुआ है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष आर. के. कलसोत्रा ने कहा कि मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने पर पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया लेकिन इस प्रदेश में मात्र 2 प्रतिशत तक ही लागू है। कितना बड़ा अन्याय है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। गुर्जर बकरवाल वहां का आदिवासी है लेकिन उन्हें राजनैतिक आरक्षण नहीं मिल रहा जबकि पूरे देश में मिला है। गत् कई वर्षों से परिसंघ की मांग है कि इन्हें राजनैतिक आरक्षण दिया जाए। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है उसे भी पहाड़ी भाषा बोलने वालों को शामिल करके कमजोर किया जा रहा है। गुर्जर बकरवाल की मांग यह भी है कि सरकारी नौकरियों में जिस तरह से अनुसूचित जाति का भर्ती अंतरराज्य स्तर पर है उसी तरह से इनका भी किया जाए। वर्तमान में इनके लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती अंतर जनपद में ही लागू है और इसलिए दूसरे जिले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

आर. के. कलसोत्रा ने आगे कहा कि आगामी 25 मार्च को विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज को इसका नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में फैसला लिया गया कि प्रत्येक जिले एवं तहसील अभी से पूरी तैयारी में लग जाएं ताकि 25 मार्च को जम्मू की सड़कें जाम हो जाए ताकि सरकार हमारी वाजिब मांगों को माने।

फिल्म मुहूर्त का समापन

सुनील पारछा

मैज इंडिया फिल्मस ने अंबेडकर भवन, नई दिल्ली में गत् दिनों 21 फरवरी, 2013 को अपनी आगामी फीचर फिल्म का मुहूर्त कार्यक्रम का आयोजन किया। गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय डॉ. उदित राज जी ने फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील पारछा के इस प्रयास को सराहा और विश्वास दिलाया कि वह इस फिल्म को जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, को पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे।

डॉ. उदित राज ने फिल्म की पठकथा की तारीफ की और सकारात्मक उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले समय में इस फिल्म के माध्यम से नारी जीवन को एक चेतना भी मिलेगी।

प्रोड्यूसर–डाइरेक्टर सुनील पारछा इसी साल तीन और फिल्म लांच करने जा रहे हैं। मैज इंडिया फिल्मस के बैनर तले बनने वाली ये तीनों फिल्में समाज को शिक्षा देने व जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। फिल्म मुहूर्त के अवसर पर चीफ गेस्ट श्री राजकुमार वैरका जी, उपाध्यक्ष, नेशनल कमीशन ऑन फॉर एससी), श्री सुनील वैद्य (विधायक), श्री विनोद कुमार, श्री नेतराम नारायण, श्री एस. पी. राय, श्री एस. पी. सिंह, श्री ओ. पी. शुक्ला, श्री बालकिशन महार, श्री कमल चन्दोलिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। साथ ही सफाई कर्मचारी आयोग, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री हरनाम सिंह जी एवं सदस्य श्री हरी राय सुद जी भी शामिल हुए।

इन सभी बुद्धिजीवियों ने फिल्म को एवं श्री सुनील पारछा के द्वारा उठाए गए इस साहसी कदम को काफी सराहा और हर मुमकिन सहायता देने का भी विश्वास दिलाया।

अनुसूचित जाति का 41737 करोड़ एवं जन जाति का 17051 करोड़ रूपये का बजट में घपला

डॉ0 उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने कहा कि देश के वित्तमंत्री श्री पी.चिदंबरम ने 28 फरवरी को 2013–14 का बजट प्रस्तुत किया। अनुसूचित जाति एवं जन जाति को जितना पैसा मिलना चाहिए था उसका लगभग आधा ही मिला और यह धांधली गत् कई सालों से चली आ रही है। शेड्यूल्ड कास्ट सब–प्लान (SCP) के अनुसार इन्हें आबादी के अनुपात में बजट से पैसा आबंटित करना चाहिए था। 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की आबादी 16.2 प्रतिशत है लेकिन आरक्षण एवं अन्य सरकारी सहूलियतें देने के लिए अभी भी 15 प्रतिशत का ही मानदंड माना जाता है। आज की योजनागत् बजट की राशि 555322 करोड़ रूपये है और यदि 15 प्रतिशत के हिसाब से भी देखा जाए तो अनुसूचित जाति को 83298.3 करोड़ रूपये मिलना चाहिए था जबकि 41,561 करोड़ रूपये का ही प्रावधान किया गया है। यह राशि लगभग आधी ही बनती है अतः 41737 करोड़ रूपये की लूट सीधे है।

डॉ0 उदित राज ने आगे कहा कि अनुसूचित जन जाति को 7.5 प्रतिशत का आधार मानकर ही सुविधाएं दिया जाता है जबकि आबादी 8.4 प्रतिशत हो गयी है। आज की योजनागत् बजट में इनको 24598 करोड़ रूपये ही मिले हैं और 17051 करोड़ की लूट इसमें भी है। इनकी आबादी के अनुसार इनको 41649.15 करोड़ रूपये का प्रावधान होना चाहिए था। ट्राइबल सब–प्लान (TSP) योजना के तहत बजट में पैसा इनकी आबादी के अनुसार मिलना चाहिए जबकि कभी मिलता नहीं है और यही योजना अनुसूचित जाति के संबंध में भी है। गत् कई वर्षों का घपला अगर हम देखें तो लाखों–करोड़ों रूपये में होगा। विभिन्न मंत्रालयों को कितना पैसा मिला और किन कार्यों के लिए मिला, वह बजट को विस्तार से पढ़ने पर ही पता लगेगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। बहुत संभव है कि ऐसी योजनाएं न की गयी हों जिससे इनके जीवन में आमूल परिवर्तन हो। कुल बजट अर्थात् योजना और गैर योजना राशि के हिसाब से आबंटन देखा जाए तो बहुत ही निराशा जनक बात होगी। कुल 2013–14 बजट की राशि 16,65,297 करोड़ रूपये है। सन् 2012 में कांग्रेस की ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति की आबादी के अनुसार बजट में इनके विकास के लिए प्रावधान करना कानूनी है। डॉ0 उदित राज ने कहा कि यह लूट कब खत्म होगी, यह कहा नहीं जा सकता। इस तरह से इस बजट से दलित–आदिवासी बहुत ही निराश हैं।

हिन्दुओं की हार का कारण धर्मशास्त्र थे?

केशव

आप सबको बहुत से ऐसे लेख पढने को मिल जायेंगे जिनमे धर्म ग्रंथों को वैज्ञानिक होने का दावा किया जाता है, उनके लेखों में जनमानस को ये बताने की कोशिश की जाती है विमान से लेकर रॉकेट तक के निर्माण सामग्री उनकी धर्म पुस्तकों में उपलब्ध है। इस पर मैंने पहले भी लेख 'क्या धार्मिक पुस्तकें वैज्ञानिक हैं' बताया था की विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। बेशक आज अधिकतर हिन्दू इन ग्रंथों में लिखे तथाकथित विज्ञान को लेकर गर्व करते पर ये हकीकत है की हिन्दू इन शास्त्रों से कोई भी अविष्कार नहीं कर पाए उल्टा अपने को 'सर्वज्ञ' समझने के कारण हजारों साल तक विदेशियों द्वारा गुलाम और बने रहे।

प्रथम शताब्दी के ग्रीक इतिहासकार स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ स्ट्रेबो, अनु होरेस लेनार्ड जोनिस VII पेज 61 में लिखा है 'हिन्दुओं का सैन्य विज्ञान का अर्थ केवल सीधे–सीधे लड़ना–मरना रहा है, हिन्दू लोग विज्ञानों की सही–सही जानकारी प्राप्त करने की ओर ध्यान नहीं देते, कुछ विज्ञानों जैसे सैन्य विज्ञान में ज्यादा प्रशिक्षण प्राप्त करने को पाप समझते हैं'। स्ट्रेबो ने जो कुछ लिखा वो प्रथम दृष्टि से बिलकुल सही है क्यों की नीतिशास्त्रो के लेखक ब्राह्मण थे जो युद्ध में शामिल नहीं होते थे, उन्हें युद्ध क्षेत्र के विभिन्न एवं आकस्मिक जरुरतो और विशेष सामरिक स्थितियों का सीधे ज्ञान नहीं था। अतः वे पुरानी व घिसीपिटी व्यूह रचनाओं को दोहरा सकते थे जिन्हें दुनिया के दूसरे देश बहुत पहले ही छोड़ चुके थे।

उधर, क्षत्रियों को युद्ध क्षेत्र में मात्र लड़ने का अधिकार था ना की विद्या का, विद्या पर तो ब्राह्मण का एकछत्र अधिकार था इस के कारण सैन्य विज्ञान समय के मुताबिक विकसित नहीं हो पाया, जबकि दूसरे देश के लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर और परस्थितियों के अनुरूप सैन्य विज्ञान का खूब उन्नत किया। परिणाम ये हुआ की भारत के लोग आसानी से विदेशियों के आधुनिक हथियारों के आगे घुटने टेक देते थे, हिन्दू सैनिक (सैनिक नहीं भीड़ कहिये) संख्या में ज्यादा होने के बाद भी मुट्ठी भर विदेशियों के सामने टिक नहीं पाते थे।

ब्राह्मणों ने ऐसे धर्मशास्त्रों को लिखा एवं बनाया जिससे पूरा समाज लगभग 7000 जातियों में बंट गया। सभी जातियों के अलग–अलग पेशे निर्धारित कर दिए गए। बहुसंख्यक लोगों को शूद्र बना दिया गया और इनका संबंध शासन–प्रशासन एवं ज्ञान से तोड़ दिया गया। ऐसे में ये क्यों चिंता करते कि देश पर राज किसका है। मुट्ठी भर हमलावर आते रहे और हुकूमत करते रहे। उनको बहुजन समाज अपने घरों और खेतों–खलिहानों से तमाशबीन की तरह देखते रहे। केवल एक जाति क्षत्रिय की ही जिम्मेदारी शासन–प्रशासन की थी। यही लोग युद्ध रोक सकते थे लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। हारने व भागने वालों को वीर की उपाधि से आज भी नवाजा जाता है। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में भीलों की सेना को लेकर के अकबर की सेना से लड़ाई की और जब वह घिर गया तो भाग गया। बेचारे भील गाजर–मूली की तरह काट दिए गए। राणा प्रताप को वीर कहा गया और उनकी जगह–जगह पर मुर्तियां स्थापित की जाती हैं। माना कि अकबर की सेना के सामने राणा प्रताप की फौज नहीं टिक पाई तो कम से कम राणा प्रताप को अपनी सेना का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था भले ही मौत के घाट चढ़ना पड़ता। भारत के इतिहास में ऐसे लोगों की पूजा की गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

हथियारों के क्षेत्र में आस–पास के देश प्रतिदिन प्रगति करते रहे, अपने हथियारों को ज्यादा कारगर और उन्नत करते रहे, पर हिन्दू इन सबसे आँखे मूँद कर अपने धर्म शास्त्रों में लिखे अलौकिक हथियारों को ही सर्वश्रेष्ठ समझते रहे।

1. 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस के पास 'बैलिस्ट' और 'कैटेपल्ट' जो 300 गज तक की दूरी तक पत्थर, बरछी, तीर आदि फेंक सकते थे, जिस कारण वो भारत के एक के बाद एक राजाओं को आसानी से जीतता चला गया। लेकिन भारत में ऐसा कुछ सदियों तक नहीं बन सका।

2. 1398 में जब तैमूर लंग ने दिल्ली को घेरा तो दिल्ली के सुल्तान वजीर मल्लू खां के भारतीय सैनिकों के पास हथियार के नाम पर जंग लगी तलवारे और बांस के डंडे थे।

3. 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो भी भारतीय सैनिको के पास बांस के धनुष और भाले थे जबकि विदेशियों के पास बंदूके थी।

4. 1527 में जब खानवा के युद्ध में राजपूतों के परखच्चे उड़ गए, बाबर के पास तोपे और बंदूके थी जबकि 'वीर' राजपूतों के पास हथियारों के नाम पर भाले और जंग लगी तलवारे थी, कईयों के पास तो केवल लाठियां थी। बाबर की तोपों ने देखते ही देखते राजपूतों की विशाल भीड़ को गाजर–मूली की तरह काट दिया। एक लाख से अधिक राजपूतों की भीड़ मात्र बीस हजार से भी कम बाबर के सैनिकों के सामने नहीं टिक पाई, जबकि 500 से अधिक हाथियों की फौजे भी थी सांगा के पास।

प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरदार ने लिखा है 'जैसे ही प्रचंड कोलाहल करती राजपूतों की विशाल भीड़ बाबर की ओर बढ़ी उन्होंने बिजली का सा प्रकाश होते हुए देखा, फिर भयानक गर्जना होते सुनी और अंत में धूमकेतु सा कुछ हवा में होता हुआ विशाल गर्म पत्थर उनके मध्य में आके गिरा, उस पत्थर के रास्ते में जो कुछ भी आया उसके परखच्चे उड़ गए, यहां तक की उसके सामने हाथी भी नहीं टिक पाए ...ये उस्ताद अली कुली की बड़ी तोप का पहला गोला था।

जो घुड़सवार बाबर के निकट पहुंच गए थे वे छोटे अग्नि स्फुरण से मारे गए, ये अग्नि स्फुरण भारतीय सैनिकों को छर्रों के समान तितर–बितर कर रहे थे ...ये बन्दुक की गोलियां थी। राजपूतों ने ऐसे हथियार पहले कभी नहीं देखे थे, देखते ही देखते लाखों राजपूतों की भीड़ इन हथियारों के सामने ढेर हो गई(भारत का सैन्य इतिहास, पेज 66)।

सोचिये क्या दशा रही होगी राजपूतों की जब उन्होंने पहली बार तोपों और बंदूकों को देखा और उसके

गोले और गोलियां खा के मरे होंगे? क्या असर पड़ा होगा हाथियों और घोडों पर जब उनके बीच तोप का गोला फटा होगा?

5. विडंबना देखिये, पिछली हारों से कोई सबक न लेकर राजपूत आगे भी अन्धविश्वास के कारण वही गलतियाँ जो सिकंदर से लेके अब तक करते रहे वही दोहराते रहे, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास न तो कोई बन्दुक थी और न ही कोई तोप जबकि अकबर के पास आधुनिक बंदूके और तोपे थी। तो कहने का मतलब ये है की अगर हिन्दू अपने धर्म ग्रंथो को 'सर्वज्ञ' और 'वैज्ञानिक' के झूठे घमंड में न रहते तो वो भी आधुनिक हथियार बना के दुश्मनों को उनके मांद तक खदेड़ और मार कर आते, और देश गुलाम होने से बच जाता, पर हिन्दू अपने झूठे अभिमान के कारण न कर सका और अपने धर्मग्रंथो में लिखी बातों से ही चिपटा रहा। अब भी ये ब्राह्मण अपने धार्मिक पुस्तकों में बदलाव करने को तैयार नहीं हैं। तमाम सामाजिक कुरीतियां और जाति–पाति बनाए रखने में ही प्रयासरत रहते हैं। चाहे जितना इसका कुप्रभाव शासन–प्रशासन और राजनीति पर पड़े, फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है।

इसके अलावा एक और कारण था जिसको नकारा नहीं जा सकता और वो है आपस में लड़ना–मरना, जिसका फायदा दुश्मनों ने खूब उठाया और इसका कारण भी ये धार्मिक पुस्तकें थी। इन्हीं धार्मिक शास्त्रों में लिखे होने के कारण क्षत्रियों के लिए अश्वमेध करने का अति लुभावना व पुण्यप्रद काम करने के लालच और कालिदास के 'यषसे विजिगीशुणाम' (अर्थात रघुवंश के राजा यश प्राप्त करने के लिए आस–पड़ोस के राजाओं को जीतते थे), इसका परिणाम ये हुआ की भारत के राजा लोग आपस में लड़ने–मरने लगे, उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और आपसी फूट होने के कारण आसानी से हारते रहे। कई बार तो अपने पड़ोस के राजा को हराने के लिए ये लोग स्वयं ही विदेशियों को बुलाते थे, जैसे की राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था।

(साभार– नवभारत टाइम्स)

आगामी 25 मार्च को जम्मू विधान सभा का घेराव

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, प्रदेश इकाई, जम्मू के नेतृत्व में एससी/एसटी, ओबीसी तबकों के बेहतरी की मांगों को लेकर 25 मार्च, 2013 को विधान सभा का घेराव किया जाएगा। जम्मू के प्रेस क्लब पर हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर जम्मू विधानसभा की ओर कूच करें। अंत में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

हमारी मुख्य मांगे– 1. नौकरियों, पदोन्नति में आरक्षण को पूरा का पूरा लागू करना, 2. एससी/एसटी प्लान को लागू करना, 3. मंडल कमीशन का 2 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक लागू करना, 4. शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राजनीतिक आरक्षण दिलाना एवं अन्य।

संपर्क :

आर. के कलसोत्रा

प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर

09419182452

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

रिटेल एफडीआई का सच

देविंदर शर्मा

यह मौजूदा मुद्दा में सबसे विवादित मुद्दा है। एक ऐसे समय जब राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बार–बार कह रहे हैं रिटेल में एफडीआई को अनुमति देना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे निवेश आएगा। विकास दर छह प्रतिशत से नीचे आ जाने के बाद आर्थिक इंजन को चलाने के लिए उन्होंने अपनी सरकार तक को दांव पर लगाने की बात कही थी। सवाल यह है कि रिटेल में एफडीआई से कितना विदेशी निवेश आने की संभावना है?खुद सरकार के अनुमान के मुताबिक अगले पांच साल में मात्र तीन अरब डॉलर (करीब 16,500 करोड़ रूपए) ही देश में आने की संभावना है। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पिछले दिनों वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) को चेताया है कि उनके पास जो ढाई लाख करोड़ रूपए की नकदी है उसे अर्थव्यवस्था में निवेश करें।

केवल पीएसयू ही नहीं, भारत का निजी उद्योग जगत भी नकदी के ढेर पर बैठा हुआ है। इसे पूंजी की जमाखोरी कहें या अतिरिक्त पूंजी, पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भारतीय कंपनियों के पास 9.3 लाख करोड़ (166 अरब डॉलर) की नकदी या फिर ऐसे निवेश थे जिन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है और बाद भी सरकार रिटेल में एफडीआई खोलने के लिए पूरा जोर लगा रही है, जबकि इससे अगले पांच वर्षों में महज तीन अरब डॉलर मिलने की ही संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में भयानक रूप से गलत हो रहा है।

पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाएं। यह समझ से परे है कि कोई समझदार व्यक्ति खासतौर पर कोई अर्थशास्त्री या फिर नीति नियंता, इस विडंबना को कैसे उचित ठहरा सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऐसे समय में संकट में है जब अनेक उद्यमी नकदी के ढेर पर बैठे हुए है। अपेक्षा से कमजोर तिमाही में, जहां अनेक कंपनियां अपनी बिक्री के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाई हैं, 500 बड़ी कंपनियां की बैलेंस शीट में धनराशि में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इन 500 कंपनियों के पास 1500 अरब डॉलर की विपुल धनराशि जमा है। केवल आइटी कंपनी एपल के पास ही 117 अरब डॉलर की धनराशि है। यूरोप में क्या हालात हैं?अकेले यूरोप में उद्योगपतियों के हाथ में करीब 2000 अरब यूरो है। यूरोप में कामकाज करने वाली अमेरिकी कंपनियों के पास भी 2000 अरब डॉलर की राशि जमा है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि विश्व में पैसे की कोई कमी नहीं है। उद्योगपतियों के पास बेशुमार दौलत है। खजाने खाली हैं तो सरकारों के। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दूसरी बार निर्वाचन के बाद जोर देकर कहा था कि अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अमीरों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बहुत से लोगों का कहना है कि ओबामा दोबारा इसलिए जीते, क्योंकि उन्होंने बहुसंख्या की भाषा बोली, 99 प्रतिशत की। किंतु जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुआ, मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों ने अमीरों पर अधिक कर लगाने के उनके चुनावी वायदों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया।

राजकोषीय घाटा पाटने की दलील इतनी मजबूत है और राजनीतिक तबके में इसका इतना प्रभाव है कि यूरोपीय सरकारें भी यूरोप के ऋण संकट से निपटने के लिए आंख मूंदकर इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, जबकि कोई भी सरकार भ्रष्टाचार पर हमला नहीं बोल रही है, जिससे यह राजकोषीय घाटा आसानी से पाटा जा सकता है। न ही निजी कंपनियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने अतिरिक्त धनराशि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश करें। तमाम देशों में अमीरों को बचाने के लिए गरीबों कीर जेब पर डाका डाला जा रहा है।

यूरोप में करोड़ों कामगार वेतन कटौती और सामाजिक सुरक्षा में कमी के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कटौतियों के कारण मंदी बढ़ रही है ओर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है। जाहिर है, इसके कारण लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप या फिर भारत हर जगह आम आदमी उन नीतियों पर गुस्से से भरा है जो सामाजिक सुरक्षा पर कुठाराघात कर रही हैं और मंदी में लोगों का जीना दूभर कर रही हैं, किंतु क्या संकट की इस घड़ी में गरीबों को ही बलि का बकरा बना देना चाहिए?जब अमीरों के पास बेशुमार दौलत है, तो फिर गरीबों को ही संकट का खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए?आर्थिक व्यवस्था मुट्ठी भर लोगों की मुट्ठी में अपार धन जमा होने की अनुमति कैसे दे सकती है, जबकि लोगों का गुजारा भी नहीं हो पा रहा है।

जाने–माने अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केयन्स ने कभी कहा था कि गिरावट की बजाय उभार की कटौती का सही समय है। पॉल क्रुगमैन ने समाधान पेश किया है– 2010 में कुछ बाज हमारे राजनीतिक जगत के आकाश में मंडराने लगे। ऐसे समय जब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही थी और रिकॉर्ड न्यून दरों पर ऋण दिया जा रहा था, जब अर्थव्यवस्था के सिद्धांत कह रहे हैं कि हमें और चाहिए, क्योंकि कम से काम चलने वाला नहीं है, राजकोषीय घाटे के बावजूद खर्च बढ़ाया जा रहा था तब हमारे राजनीतिक वर्ग को समझाया गया कि अर्थव्यवस्था की शीर्ष वरीयता घाटा कम करना है, न कि रोजगार उपलब्ध कराना। पॉल क्रुगमैन को पढ़कर और दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों को देखकर यह है कि कुछ औद्योगिक घराने फिरौती वसूलने के लिए अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीएसयू को तो 2.5 लाख करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशि अर्थव्यवस्था में डालने को कह रहे हैं जबकि इससे चार गुणा अधिक राशि रखने वाले निजी क्षेत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे।

कुछ विचित्र कारणों से कटौती का मतलब हो गया है अमीरों और ताकतवरों को कर में छूट प्रदान करना और गरीबों पर कर लगाना। मंदी के दौरान जब सरकारों ने पूंजीपतियों को करीब 2,000 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज प्रदान किए थे, तब किसी अर्थशास्त्री ने राजकोषीय घाटे की चेतावनी नहीं दी थी। किसी भी अर्थशास्त्री ने हमें जनता के धन को बैंकों और उद्योगपतियों के बेलआउट में देने से मना नहीं किया था। यह गलत नीतियों का नतीजा है जो निजी क्षेत्र नकद के ढेर पर बैठा है और आम आदमी कटौती का दंश झेल रहा है। 20,000 अरब डॉलर की यह विपुल धनराशि सरकारों के खजाने से निकलकर बड़े व्यापारियों के हाथों में पहुंच गई। एक कठिन समय में जब इस धन की जरूरत जनता के लिए रोजगार उपलब्ध कराने, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए थी, तब यह अमीरों की जेब में चला गया। पूरा आर्थिक तंत्र पूरी तरह गलत सिद्धांत– 'मुनाफे का निजीकरण, लागत का सामाजीकरण' पर चल रहा है।

(लेखक आर्थिक नीतियों के विश्लेषक हैं)

(साभार–दैनिक जागरण)

ऑल इंडिया इन्कम टैक्स एस.सी./एस.टी इम्प्लाइज वेलफेयर फेडरेशन का चुनाव सम्पन्न

विनोद कुमार

आयकर विभाग का अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के आंदोलन को सन् 1997 से पुरजोर समर्थन मिला था। उसका कारण यह भी था कि डॉ0 उदित राज इसी विभाग से थे। उनकी सक्रियता पहले से ही आयकर विभाग में रही है, जब 5 आरक्षण विरोधी आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किये गए तो उस समय एक नेतृत्व की आवश्यकता अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारी–अधिकारी महसूस किये और अंततः उस समय के राम राज को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। डॉ0 उदित राज ने 2003 में आयकर विभाग से जब इस्तीफा दिया तब से ऑल इंडिया इन्कम टैक्स एस.सी./एस.टी इम्प्लाइज वेलफेयर फेडरेशन की गतिविधियां शिथिल हुईं और धीरे–धीरे न के बराबर पहुंच गयीं। गत् कई वर्षों से जहां भी डॉ0 उदित राज देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हैं, आयकर विभाग के लोगों की शिकायत आती रही कि उन्होंने विभाग को क्यों छोड़ दिया?इस पीड़ा से वे व्यथित रहे और जब अवसर आया तो फिर से आयकर विभाग के संगठन को 23 फरवरी, 2013 को गठित किया गया।

23 फरवरी को आंध्रा एसोसिएशन, लोधी रोड, नई दिल्ली में देश के कोने–कोने से आयकर विभाग के कर्मचारी–अधिकारी एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उ0प्र0, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड आदि प्रदेशों से प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बहुत दिनों से सही नेतृत्व का अभाव रहा है और अब आयकर आयुक्त प्रीता हरित ने इसकी कमी पूरी कर दी है। प्रीता हरित बचपन से ही समाज की सेवा की भावना रखती थी और जैसे ही अवसर मिला, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आयीं। वे एक साहसी और मिशनरी व्यक्तित्व की धनी हैं और आशा है कि आयकर विभाग का संगठन उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पर डॉ0 उदित राज ने छोड़ा था। डॉ0 उदित राज ने श्रीमती प्रीता हरित को ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन सभी ने जोर–शोर से किया। नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर अनुसूचित जाति/जन जाति कर्मचारियों व अधिकारियों की तैनाती गलत स्थानों पर की जा रही है। जो ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की पॉलिसी डॉ0 उदित राज के समय में बनी थी, उसे कुछ वर्षों तक तो लागू किया गया लेकिन संगठन की सक्रियता के अभाव में फिर से भारी धांधली होने लगी है। अभी तक एक भी एस.सी./एस.टी. समाज से बोर्ड का मेंबर एवं चेयरमैन नहीं हुआ है और अब इस दिशा में सार्थक प्रयास करने होगें। विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी समाज के हित में बाहर आंदोलन चल रहे हैं, उसे समर्थन दें। परिसंघ निजी क्षेत्र एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है और अब आयकर विभाग के संगठन से पूरा सहयोग मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। प्रीता हरित के अतिरिक्त जिन प्रमुख लोगों को चुना गया, वे निम्नलिखित हैं :–

मुख्य संरक्षक : डॉ0 उदित राज
संरक्षक : बी.सी. मीणा, आईआरएस
एवं सुबचन राम, आईआरएस
अध्यक्ष : प्रीता हरित, आईआरएस
उपाध्यक्ष : राम अवतार गौतम
महासचिवः अरविंद एस. रामटेके
सचिव : पी.एस. कनौजिया, राम पाल, एवं अन्ना मेश्राम,
कोषाध्यक्ष : रमेश चन्द्र
सह कोषाध्यक्ष : नैन सिंह

बांये से प्रीता हरित, डॉ. उदित राज, राज कुमार वेरका (उपाध्यक्ष, अनसुचित जाति आयोग)।

There is a Scam of Rs. 41737 crore for SCs & Rs. 17051 crore for STs in 2013-14 Budget

Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations said that the Budget for 2013-2014 has been presented by the Finance Minister, Shri P. Chidambaram today the 28th February, 2013. The allocation earmarked for SC/ST people in this budget is half of the intended allocation and this highhandedness has been going on for several years. According to the Scheduled Caste Sub-Plan (SCP), the allocation for the Scheduled Caste people should have been in proportion to their population. According to the 2001 Census, population of the Scheduled Caste people is 16.2% of the total population but for the purpose of allocation of funds for reservation and other Government benefits, the yardstick continues to be 15%. In this budget, the total amount of the Plan budget is Rs. 5,55,322 crore and even if it is calculated on the basis of 15% , the allocation for Scheduled Castes should have been Rs. 83,298.3 crore whereas provision in the budget for this purpose has been made for just Rs. 41,561 crore.This works out to just half of the figure of Rs. 83,298.3 crore.Thus there is a big scam of Rs. 41,737 crore.

Dr. Udit Raj further said that the allocation for Schedled Tribes in the budget is made taking their population to be 7.5% when actually their population has increased to 8.4% . In the Plan Budget, a sum of Rs. 24,598 crore has been earmarked for Scheduled Tribes and here also there is a scam of Rs. 17051 crore. In proportion to their population, for the Scheduled Tribes, there should have been an allocation of Rs. 41,649.15 crore According to the Tribal Sub Plan (TSP), the budget allocation should have been in proportion to their population whereas it has never been done so and the same policy holds good for Scheduled Castes. If we take into account this type of scam which has been going on for several years, then the amount will run into several lakh crores. The exact allocations for different Ministries under different heads can be known after a detailed study of the budget and only then some comments can be made. It is quite likely that schemes which could bring about far-reaching changes in the lives of SC/ST people might not have been made. If allocations are viewed after taking into account the total amount of the budget including non-plan amount, the situation is very desperate. The total budget amount for 2013-214 is Rs. 16,65,297 crore . In the year 2013, the Congress Government in Andhra Pradesh made a law that allocations in the budget for the development SC/ST people should be in proportion to their population. Dr. UIdit Raj said that it is difficult to say when this scam will end . Thus, Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are extremely dissatisfied with this budget.

20 अप्रैल को झूलेलाल मैदान, नजदीक-लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में
विशाल रैली
अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, पासवा महासंघ व अन्य के नेतृत्व में पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए 20 अप्रैल, 2013 को प्रातः 10 बजे झूलेलाल मैदान, नजदीक-लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को मुख्य रूप से डॉ0 उदित राज जी सम्बोधित करेगें। आप सभी से निवेदन है अपने अधिकारों को सुरक्षित कराने एवं समतामूलक भारत के निर्माण हेतु साथियों सहित पहुंचकर रैली को सफल बनाएं।

कौशल किशोर
पूर्व श्रममंत्री,
रा. अध्यक्ष, पा. महासंघ
9415005536

पी.सी. कुरील
राष्ट्रीय संयोजक,
रा. भागीदारी आन्दोलन
9415024510

भवन नाथ पासवान
प्रदेश अध्यक्ष
अजा/जजा परिसंघ
9415158866

एससी/एसटी छात्रों का दो दिवसीय राष्ट्रीय छात्र नेतृत्व शिविर
दिनांक : 9–10 मार्च, 2013, स्थान– नांदेड़, महाराष्ट्र
मुख्य मार्गदर्शक– डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
व
डॉ. इंदिरा अठावले, प्रधान महासचिव व प्रदेश अध्यक्ष(महाराष्ट्र), परिसंघ।
संपर्क
हर्षवर्धन दवणे
मो.–07709975562

SCs, STs don't get their share of the pie

Subodh Varma

NEW DELHI: One of the most shocking features of the budgetary process is the way funds mandated for spending for the benefit of dalits and adivasis are manipulated, diverted or frittered way. This has been going on for years, and as new research shows, continues today in more and more imaginative forms.

Dalits and adivasis together make up about a quarter of India's population. In view of persistent poverty, lack of education, poor health outcomes and low paying jobs, not to forget brutal discrimination, a majority of these communities were to be given special attention through various government schemes.

One of these is the Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) and its complement, the Tribal Sub Plan (TSP) under which all government ministries are mandated to spend about 16% of their funds on dalits and 8% on adivasis, respectively. This was to apply to state as well as central governments. Recent research done by the Centre for Budget and Governance Accountability, a Delhi based advocacy group, and its partner organizations shows a picture of multiple ways in which this is being violated by states.

In Bihar and Rajasthan, a study by the National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) found wide divergence between annual plans and the fine print in the budget documents. Thus Bihar with 15.7% dalit population, showed an allocation of 16.9% for SCSP in the annual Plan for 2010-11, but its budget documents were showing the reality of just 1.2%. In Rajasthan too, with a share of 17% dalits in the population, the annual plan showed 16.4% allocation for SCSP but the budget documents showed a mere 3.9%. A similar story was repeated for adivasis in the TSP.

A study of Odisha, MP and UP by NCDHR showed up another gambit: the funds are earmarked for dalits and adivasis as required, but they are spent on other things. In MP, earmarked funds for dalits were spent on: buying furniture and equipment for homeopathy and ayurvedic clinincs, constructing irrigation channels, even a whopping Rs 236 crore on building bridges and highways, and so on. In UP, a chunk of SCSP funds were recorded as spent on 'grants in aid' with unclear details. Over 17% of these funds were spent on 'large scale construction' while nearly five percent was spent on salaries though the guidelines clearly say that SCSP funds are not to be used for salaries.

In Gujarat, an Ahmedabad based NGO Pathey discovered examples of TSP funds used for general purposes: Rs.5 crore was spent to mark Swami Vivekanand's 150th Birth Anniversary and Rs.170 crore was used to build basic infrastructure like schools, toilets, markets etc. in urban areas. Then there is the standard way of earmarking on paper but actually not spending the amount. According to an answer given in Parliament in December last year, states were not spending about Rs.10,000 crore every year from their own outlays in SCSP.

The central government itself creates a similar fog around earmarked spending for dalits and adivasis. Till a few years ago, many ministries were just refusing to spend any money directly for these sections. Others who claimed they had spent it as per law, were actually spending it for the general public and retrospectively claiming in the books that since dalits and adivasis were also present in the general population, they had received benefits as required!

After the Narendra Jadhav committee said in late 2010, that only 25 ministries/departments for TSP, things don't seem to have improved. In 2012-13, dalits were deprived of about Rs. 26,233 crore worth of development funds while adivasis were similarly deprived of about Rs. 9572 crore. Despite all the promises to fix the problem, it persists.

(Courtesy Times of India)

J&K UNIT OF THE CONFEDERATION TOOK SOME CRUCIAL DECISIONS AT JAMMU

The J&K unit of the All India Confederation of SC/ST Organizations held a State level conference at the Gurjar Trust building on 17.2.2013. Jammu & Kashmir is the only State in India which has a Constitution of its own. On the 26th October, 1947, it was included in the Indian Union. On the one hand, this State is considered as part of India and on the other hand, laws passed by the Parliament of India are again ratified by the J&K State Assembly. SC/ST employees and officers of this State are deprived of the facility of seniority and its resultant benefits. The J&K High Court did not accept the judgement delivered by the Supreme Court in the Nagraj case and introduced the catch-up rule. "Catch-up" rule means that even though SC/ST employees and officers do get the benefit of seniority in the matter of reservation in promotions but they cannot get further promotions till the general category employees and officers, who were earlier on par with them, are promoted. As a result of the 85th Constitution Amendment, the benefit of seniority and its resultant benefits were restored but the same has not so far been enforced in this State.

While addressing the Conference, Shri R.K. Kalsotra, State President of the J&K Unit of the Confederation, said that at the time of implementation of the Mandal Commission recommendations, while OBCs were given 27% reservation in other States, in J&K, only 2% reservation was given for OBCs which is a gross injustice. Gurjar Bakarwals are Adivasis of the State of J&K but they are deprived of political reservation where as it is available in the rest of the country. For the last so many years, the Confederation has been demanding that Gurjar Bakarwals may be given the benefit of political reservation. Reservation in Government jobs has been further diluted by including by the people of the State who speak Pahari dialect. Gurjar Bakarwals have also demanded that just as reservation in Govt. jobs is available for SC/ST employees and officers from all parts of the State, it should be done in the similar way for Gurjar Bakarwals.At present, reservation for Gurjar Bakarwals is available only at the district level. i.e. within each district and do not get the benefit of inter-district reservation.

Shri R.K. Kalsotra further said that on 25th March, 2013, a huge rally will be organized under the leadership of Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations. It was also resolved at the Conference that workers from each and every tehsil and district in the State should make all out efforts to ensure that on the 25trh March, 2013, all Jammu roads are blocked so that the State Government is forced to accede to our demands.

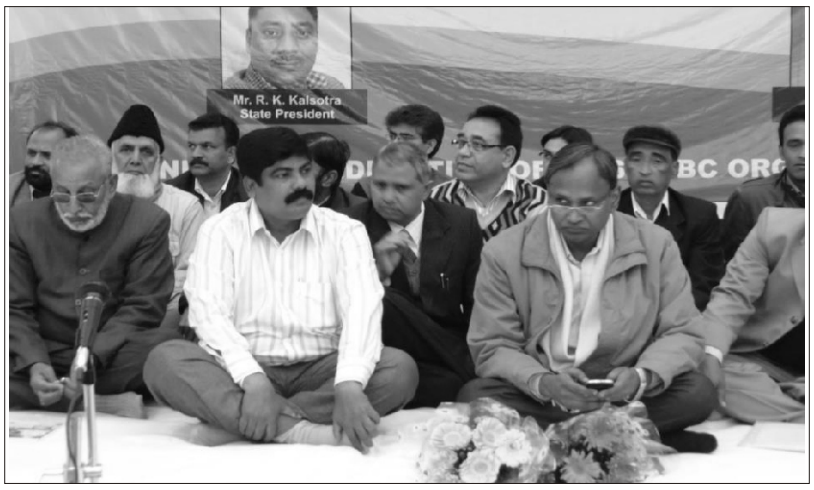

Election of All India Income Tax SC/ST Employees Welfare Federation held

Vinod Kumar

This organization has been supporting the movement of All India Confederation of SC/ST Orgainsations since 1997 by all means and ways. The main reason was that Dr. Udit Raj was from this department. He revived All India Income Tax SC/ST Employees Welfare Federation in Income Tax department and before that there was almost no activity. This gave popularity to Dr. Udit Raj, that time he was known as Ram Raj and when five anti reservation orders were issued by Department of Personal and Training in 1997, the search for a dynamic leader was felt by almost all SC/ST Employees in different govt. departments. Based on such needs, he was selected as National Chairman of All India Confederation of SC/ST Organisations. Dr. Udit Raj remained active in Income Tax Department till 2001 and after that, got so much preoccupied with other activities and fewer activities were left. He resigned from the department in 2003 and after that the force of Income Tax Federation went down and down. In recent past years, Dr. Udit Raj was approached by the employees and officers of Income Tax Department that why did he turned back? He was moved and felt to revamp the federation again. For last two years, hectic consultations were made that how to reorganize it? 23rd February, 2013 came as an occasion to accomplish the goal.

The employees and officers of Income Tax department joined together on 23rd February, 2013 in Andhra Association, Lodhi Road, New Delhi. The representatives from Madhya Pradesh, U.P., Maharashtra, West Bengal, Bihar, Delhi, Andhra Pradesh, Haryana, Chandigarh and Jharkhand participated the meet. The need of an appropriate leader was felt for long time and Ms. Preeta Harit, Commissioner of Income Tax filled this vacuum. She had been nurturing the spirit to serve the society from her childhood onwards. On getting proper opportunity, she swung into action and accepted the challenge to lead the federation. She is quite courageous and harbours the missionary zeal. She was proposed as president of Federation at national level and over whelming support came in her favour. Now there is hope to activate the federation to the same height where Dr. Udit Raj left. Before 1997-98, most of SC/ST employees were posted on non significant places like salary and TDS and this was vehemently opposed by federation. A new guideline for posting was issued and everyone was given opportunity to serve in both places- significant and non significant both for a fixed tenure. The SC/ST employees and officers were benefited greatly by this new transfer and posting policy. Ever since, the activity of federation slowed down, again manipulation has began and now many employees and officers belonging to SC/ST are in receiving end. So far, no SC/ST officer has reached to the level of CBDT (Board) where policies are framed. The federation will take up this issue on priority basis. The new leadership of federation will see to it that the outside nationwide struggle will be supported whole heartedly. Due to globalization and privatization, the reservation in private sector is only alternative to maintain the progress achieved by these communities and now there is hope that full-fledged support will be rendered to All India Confederation of SC/ST Organisations. The names of following principal office bearers of Federation are being mentioned below :-

Ms. Preeta Harit, President, Federation

Chief Patron : Dr. Udit Raj
Patron : B. C. Meena, IRS & Subachan, IRS
President : Preeta Harit, IRS
Vice President : Ramavtar Gautam
General Secreatry : Arvind S. Ramteke
Secretaries : P. S. Kannujia, Rampal & Anna Meshram
Treasurer : Ramesh Chand
Sub-Treasurer : Nain Singh

INDIA IS BLEEDING ON THE THORNS OF SEXUAL VIOLENCE, RUDDERLESS LEADERSHIP AND INEPT BUREAUCRACY

R. L. Khanna

We need to hang our heads in shame for the most abominable act of the Nirbhaya gang rape and murder which has happened in the Capital of our blessed land, Bharat , where respect and esteem for women folk is supposed to be deeply rooted in our cultural ethos. India must be the only country in the world against whom advisories have been issued by United States of America and China to advise its citizens to avoid visiting India on account of the frequency of the rape and other sex crimes. Credit for exposing the Government for its utter failure on this account largely goes to people's outburst against such heinous crimes. Nirbhaya's case is just one instance which has come to limelight. Sex crimes against Dalit women and other weaker sections are a frequent happening and most of them are either not reported or go unpunished. On the front of sex crimes like that of many other areas, the degeneration of values has reached its nadir. Of course, there have been wide-spread protests and condemnation of this ghastly act but there appears to be no let up in such crimes as is evident from the newspaper headlines which has forced the Government to act fast by announcing the appointment of Justice Verma Committee and come out with a comprehensive solution to deal sternly with this problem. The Verma Committee recommendations on this issue have dealt with the subject candidly and has made some very cogent and forthright recommendations to hold a public debate, both inside and outside the Parliament on this vexed and mind-boggling issue so that necessary changed could be made in our legal system to handle this menace effectively. While dealing with this issue, our Hon'ble President, Shri Pranab Mukherjee, in his maiden Presidential address has rightly urged the nation to "reset its moral compass" and stressed the " urgent need for ensuring gender equality for every women as the price of neglect will be high ". The issues relating to resetting of our moral compass for gender equality etc. and how the moral degeneration has come to such a pass in Independent India will be discussed and analysed later in the article.

As a result of the avalanche of protests from people from across the country, in general and the civil society and the media in particular against the perpetrators of Nirbhaya type of gang rapes and murders, the Government of India was forced to promulgate The Criminal Law (Amendment) Ordinance 2013 Ordinance hastily and half-heartedly which is nothing new but old wine in a new bottle . This Ordnance has left out all the well thought out recommendations of the Verma Commission for the empowerment of women. The Ordnance largely incorporates provisions of the earlier Criminal Law Amendment Bill 2012 with some innocuous changes here and there. While several organizations and social activists have expressed their dis-satisfaction with the provisions of the Ordinance and continue to keep pressure and protests for their demands on this issue, the Government through its learned Minister, Shri Chidambaram has come out with a lame excuse that some of the recommendations of the Verma Committee are difficult. The Hon'ble Minister is perhaps fully aware that the people of India are already passing through a very difficult period as far as crimes relating to sexual violence are concerned and a decision on some of the important left-out recommendations of the Verma Committee could not be set aside in this slip-shod manner.

A review of some of the strong recommendations of the Verma Committee which have been ignored by the Government would have dealt a deadly blow to the nefarious designs of certain categories of perpetrators of the crimes relating to sexual violence. For example, it is perfectly all right if a superior officer in the Police force or Army is held responsible for an offence relating to rape in police custody or sexual assault committed by his junior colleague. It will only make senior officers more responsible towards their duties for implementing Government and Public policies effective.Again, Verma Committee's recommendation that no sanction be required to prosecute public servants accused of sexual violence will go a long way to curb this menace as there is an increasing number of instances, both reported and unreported, of sexual violence among public servants. With a view to save these public servants from false and baseless complaints and attempts of character assassination, suitable provisions can be made in the law to deal with such cases. Similarly, Varma Commission has made very strong recommendations like disqualification against sitting and contesting legislators which have unfortunately been ignored by the Government.There are roughly 260 MLAs and MPs contested polls while facing sexual assault charges.

The Hon'ble President has very aptly urged the Indian people to rest their moral compass and stressed the urgent need for ensuring equality for every woman. Even though almost all the religions practised by the people in India preach against violence and disrespect towards women in varying degrees, yet there has been steep degradation in moral values including character and integrity particularly after Independence. We have to analyze the reasons objectively. Since Independence, the political class has not been laying much emphasis on moral values and character building either at school or college level or in public life.It marked the beginning of the decline in moral values and integrity when a few public men called on a former Prime Minister and complained against the corrupt practices of Chief Ministers of some States and he ignored it by saying that the money amassed by the corrupt politicians was after all at Delhi Secretariat) , remaining in the country and afterwards, corruption in these States and later on in other States started increasing by leaps and bounds. Our social fabric is so much afflicted with moral turpitude, corruption and violence including sexual violence that no group or section appears to be unaffected by this malice. You name any section or group of the society, be it the political class, executive, judiciary, corporate houses, media, academia, etc. corrupt is rampant everywhere. Corruption in cash or kind and violence including sexual violence are intricately intertwined.

On the sexual violence front, some of the time tested Indian cultural values like shunning pre-marital sex, practising monogamy laced with moral values could greatly help not only in dealing with this explosive situation of sexual violence but would also help check the spread of dreaded diseases like HIV on account of immoral sex. Corruption in cash or kind in public life also gives rise to all sorts of social evils including sexual violence. Wrong Government policies on some of the crucial issues concerning citizens are also largely responsible for many social evils. On the one hand, Government openly propagates the use of condoms easily available through condom machines (one such machine is installed chemist shops and public display boards in the name of safe sex, particularly the youngsters for pre-marital and extra-marital sex while at the same there are display boards which say that immoral sex leads to diseases like HIV. Such is the confusion being created by Government policies. 42% of the population of the country comprises of children and they are the most neglected group and least safe. Every day nearly 200 children are kidnapped in the country according to a PIL filed in Delhi High Court .who are mostly used for trafficking and other crimes. Response of most of the State Governments and the Govt of India to this gargantuan problem is lackadaisical.This is the greatment being meted out to the future of the country. It is a wake-up call for the political class to save the country's future generation from going to dogs.

Our country is really bleeding on the thorns of sexual violence, rudderless leadership and inept bureaucracy. If the political class does not rise to the occasion, there is every likelihood that there will be a chaos which could, God forbid, lead to a civil war. The swollen-headed bureaucracy with fat pay-packets and very liberal perks has to shed a lot of flab and start delivering to fulfill aspirations of the teeming millions.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 7 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 28 February, 2013

जहां मन हिंसा से मुड़ता है, वहां दुःख अवश्य ही शांत हो जाता है।

-गौतम बुद्ध

CRUCIAL DECISIONS TAKEN AT JAMMU BY THE NATIONAL WORKING COMMITTEE OF CONFEDERATION

Dr. Udit Raj

Immediately after the State level Conference of the All India Confederation of SC/ST Organizations was concluded at Jammu on 17.2.2013, the meeting of the National Steering Committee was started which lasted till 3 P.M. on 18.2.2013. The major points of discussion at the National Working Committee meeting were about the ways and means to organize the SC/ST/OBC youths and students, utilization of social media, cadre-building and to coordinate the activities of the Dalit-Adivasi businessmen. For the last so many years, the Confederation has been relentlessly fighting for reservation in the private sector but we have so far not been able to bring the real stakeholders and beneficiaries of the proposed scheme as a united force. Many of the leaders in the Confederation are getting old and many office bearers and workers have also retired. The number of new entrants into the Confederation has not been in proportion to the leaders who have retired which has been a mistake on our part. The number of jobs has shrunk due to privatization and on the other hand, there has been an increase in the number of educated youths. In this background, it is not difficult to realize the urgency of reservation in private sector. Whether it is Anna's or Kejriwal's campaign or more recently public outcry against Nirbhaya's rape and brutal murder, the youths and students have played a significant role even though none of these issues was directly related to them. Reservation in private sector not only directly benefits Dalit/Adivasi youths and students but their very existence depends on this factor. In the present context, the situation is such that unless there is reservation in the private sector, education for SC/ST youths is meaningless. A huge rally was held at Nanded in Maharashtra on 10th January, 2013 under the leadership of Harshvardhan Davane where it was resolved to raise an army of 1 lakh SC/ST youths and students from all over the country. It is incumbent on workers and office bearers of the Confederation to bring maximum number of SC/ST students and youths from their areas for this purpose.

We have been fighting whole-heartedly for the rights of SC/ST people continuously for the last fifteen years due to which cadre camps could not be held. Cadres play the same role for the cause of any campaign which is played by blood in the veins of human body. Some employees and officers have done great harm to the organization in the name of cadre building. They went on raising cadres and collecting funds became their prime activity and holding just one conference annually. They make big speeches against Brahminism but their contribution towards the struggle in nil. Who is not aware of this stark reality that without ideology, preaching does not have much of a meaning and without preaching , ideology is also meaningless. We were marching forward by striking a balance between ideology and practice but the manner in which the workers had to be trained and built, was not upto the mark. This job can be done by holding cadre camps . So far, Haryana, Jammu & Kashmir and Uttarkhand units have taken the responsibility of holding cadre camps. Office bearers have also been asked to send their views as to what type of study material is required in the present circumstances for holding cadre camps. Units of all the the States should accomplish the job of holding cadre camps by May, 2013.

National print and electronic media are busy day in and day out news items which strengthen the cause of Brahminism. They pick up any controversial issue and keep on broadcasting the same continuously which hardly concerns the common man. The farmers do not come in their scheme of things and as regards publishing news items about Dalits and Adivasis, instead of highlighting their problems, they are busy building a public opinion against reservation. There was a time when ground level leaders and workers had a big role to play but the electronic media has greatly diminished their role. In a matter of seconds and minutes, they convey the messages and views of their chosen leaders. In these circumstances, views of the ground level workers and leaders take a long time to reach the public at large. Recently the issue of social media came up prominently in a Chintan Baithak of the Congress Party held at Jaipur. The Congress being such a big party understands very well the significance of social media but we are still ignorant about its importance . When the prominent national newspapers and electronic channels are not prepared to raise our issues, we are not left with any alternative except to take recourse to social media. If we have to live in this country with honour and respect then we will have to make social media a part and parcel of our life. This is a very economical and easily available media option. Face Book, Internet, Twitter, SMS, Missed Call, Website etc. are all forms of social media and the sooner we start making use of these devices for launching our campaigns and for spreading our ideology, the better it would for us to achieve our goals faster. All the workers of the Confederation and readers of Voice of Buddha are requested to send their emails and mobile numbers so that a data bank could be compiled with a view to convey our views in a matter of minutes across the country.

Not before long, it was considered that political power is the key to all other problems privileges of human life but this does not hold good any more. Big industrial houses have sprung up because of privatization and polarization . There is a tremendous increase of black money in politics which mostly comes from the big industrial houses and businessmen. When the political class takes black money from the industrial houses, then the business class will dictate their terms. It is precisely for this reason that most of the Government policies and decision are pro-business houses. Whenever the issue of reservation in the private sector is raised, it is vehemently opposed by the industrial houses. Not only this, but the situation becomes far more difficult when we become helpless to organize our campaigns and programmes for want of funds. Why should the upper caste industrialists extend financial help to us, rather they will extend their support to those people who are against us. Under these circumstances, we will have to create a team of industrialists from amongst SC/ST people to come to our rescue. Some progress has been made in social and political fields but a beginning on the economic front has yet to be made. Reservation is in danger due to privatization and we are not able to muster our full strength for this purpose. We have to make an organization of small scale business of SC/ST people and educate and treain them and make them aware of the Government facilities in this regard so that they could become successful industrialists. It is the duty of the workers of the Confederation that as far as possible, they should establish contact with SSC/ST businessmen of their area and send their names and addresses to us. We have to start shortly Confederation of Dalit Entrepreneurs.

(L to R) Vinod Kumar, Maheshwar Raj, R. K. Kalsotra, Dr. Udit Raj & Dr. Indira Athawale participating in the Confederation Meeting.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com
Computer typesetting by N. K. Karn